

प्रेषक,

डी०एस० गर्वाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पौड़ी।

राजस्व अनुभाग-३

देहरादून: दिनांक: ३० मार्च, 2016

विषय:- जनपद पौड़ी के अन्तर्गत ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन के निमार्ण हेतु ग्राम चिलगढ मल्ला, पोखरी, श्रीकोट, चिलगढ, कोठड, फरासू, स्वीत, डुगरी पंथ, पन्तलगा डुगरीपंथ, दिखोल्यूं पुराना श्रीनगर, ढामक, सौड, राजसेरालगा, बगवान लगा, भलगांव की कुल 21.534 हैं और वन भूमि भारतीय रेल विभाग, भारत सरकार को सशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-५८३४/पॉच-भूहस्ता./रा०प०/१६ दिनांक ०६ फरवरी, २०१६, पत्र संख्या-५९२७/पॉच-भूहस्ता./रा०प०/१६ दिनांक १८ फरवरी, २०१६, पत्र संख्या-६०३९/पॉच-भूहस्ता./रा०प०/१६ दिनांक ०६ फरवरी, २०१६ एवं आपके पत्र दिनांक ११ जनवरी, २०१६ एवं दिनांक ०५-०२-२०१६ के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, जनपद पौड़ी के अन्तर्गत ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन के निमार्ण हेतु ग्राम चिलगढ मल्ला, पोखरी, श्रीकोट, चिलगढ, कोठड, फरासू, स्वीत, डुगरी पंथ, पन्तलगा डुगरीपंथ, दिखोल्यूं पुराना श्रीनगर, ढामक, सौड, राजसेरालगा, बगवान लगा, भलगांव की कुल 21.534 हैं और वन भूमि भारतीय रेल विभाग, भारत सरकार को शासनादेश सं०-२५८/१६ (१)/७३-राजस्व-१ दि०-०९.०५.१९८४ एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या-१६९५/९७-१-१(६०)/९३-२८०-रा०-१ दिनांक-१२.०९.१९९७ में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत वर्तमान प्रचलित बाजार दर से निकाले गये भूमि के मूल्य एवं उक्त भूमि की मालगुजारी के 100 गुने के बराबर धनराशि एकमुश्त जमा किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन भारतीय रेल विभाग, भारत सरकार के नाम हस्तान्तरण/आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) राजस्व विभाग के शासनादेश दिनांक ९-५-१९८४ की व्यवस्थानुसार रेलवे विभाग से भूमि की कीमत प्रचलित बाजार दर से तथा मालगुजारी के 100 गुने के बराबर की एक मुश्त धनराशि भी वसूल की जायेगी।
- (2) ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना का कार्य सार्वकालिक/स्थाई प्रकृति का होने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड सरकार की गैर वन भूमि/सिंविल भूमि को रेल विभाग भारत सरकार के नाम सर्वाधिकार सहित, स्थाई तौर पर हस्तान्तरित कर दी जाय।
- (3) जिलाधिकारी द्वारा भारतीय रेल विभाग, भारत सरकार से भूमि का मूल्य एवं मालगुजारी प्राप्त कर सम्बन्धित लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा।
- (4). प्रश्नगत नॉन जेड०४० भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू-सुधार अधिनियम की धारा-१३२ के समकक्ष एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) जिलाधिकारी द्वारा राजस्व विभाग, उ०प्र०शासन के शासनादेश संख्या-२५८दि०-९.५.१९८४ के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

३१

५८२

- (6) प्रश्नगत मामले में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(NGT)के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7) इस संबंध में सिविल अपील संख्या-1132/2011 (एस०एल०पी०)/(सी) संख्या-3109 /2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (8) रिट याचिका संख्या-233/2008श्रीमती बीना बहुगुणा बनाम राज्य में मा०उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में शासनादेश दिनांक 13-11-2013 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (9) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।

अतः इस संबंध में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों की अनुपालन स्थिति से भी अनिवार्य रूप से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी०एस० गव्याल)
सचिव।

प०प०सं-०८ (१) /XVIII(III)/2016— तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
3. डिप्टी चीफ इंजीनियर, उत्तर रेलवे, मुरादाबाद, उ०प्र०।
4. संयुक्त महाप्रबन्धक, रेल विकास निगम लि०, ऋषिकेश—देहरादून।
5. निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय।
6. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे०पी० जोशी)
अपर सचिव।